on behalf of Shri Gajanand Sadashiv Potdar, claiming peusion on the basis of participation in the Delhi Conspiracy Case has since been sanctioned.

SCI Tanker Deal

*406. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a write up in the Economic Times of June 16,1993 under caption "SCI Tanker deal takes Shipping Circles by surprise";

(b) if so, what is the reaction of Govt, thereto: and

(c) whether Government have any plan to place order for tankers with the Hindustan Shipyard, Visakhapatnam to enable it to turn the corner?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir

(b) The report refers to placement of order by Shipping Corporation of India on South Korean Shipyards for acquisition of 4 Suezmax Oil Tankers at an estimated cost of US $ 65.53 Million each. The main point raised in the report is that it would have been advisable to go in for second hand Tankers taking into account the high price of new tankers. While considering the acquisition of the vessels, various factors are taken into account. These include the price of vessel, availability of finance, specific cargo requirement etc. Taking into account all these factors, it was felt that it would be better to go in for new acquisition rather than to acquire second hand tankers.

(c) Hindustan Shipyard can build ships upto about 50,000 tonnes only, whereas the crude oil Tankers are normally of the size of 80,000 tonnes and above. Thus Hindustan Shipyard is not equipped to build Tankers of the size required by the Shipping Corporation of India.

भारत और बंगलादेश के मध्य विवादास्पद द्वीप

*407. डा॰ जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री॰ राम जेठमलानी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और बंगलादेश के मध्य अनेक द्वीप अभी भी विवादास्पद स्थिति में हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने द्वीप हैं जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में हैं और उनका निराकरण किया जाना शेष है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गत वर्ष तीन बीघा द्वीप के हस्तांतरण के समय इन द्वीपों से संबंधित विवादों को भी हल करने का वचन दिया गया था ;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा गत वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) और (ख) भारत-बंगलादेश भू-सिमा करार, 1974 के अनुसार बंगलादेश में भारतीय बस्तियों और भारत में बंगला-देशी बस्तियों का आदान-प्रदान किया जाना है । सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलादेश में 130 भारतीय बस्तियां और भारत में 95 बंगलादेशी बस्तियां हैं ।

(ग) जी हां । सरकार भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार, 1974 से सम्बन्धित अनसुलझे मसलों को शीघ्र हल करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें बस्तियों के आदान-प्रदान का मसला भी शामिल है । 26 मार्च, 1993 को संसद में अपनी ओर से दिए गए वक्तव्य में यह बात दोहराई गई थी कि सरकार 1974 के करार के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए वचनबद्ध है ।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में प्रयास किए जा रहे हैं कि इस मामले के क्रियान्वयन में शीघ्र प्रगति हो । इस विषय पर बंगला देश की सरकार के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता रहा है । 1974 के करार के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कानूनी तथा संवैधानिक कदमों की अन्य मंत्रालयों के परामर्श से विस्तार से जांच की गई है और इसके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को विदेशों से प्राप्त वित्तीय सहायता

*408. श्री राम जेठमलानी :
डा॰ जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कार्यरत हजारों स्वैच्छिक संस्थाओं को विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो देश में धर्म-प्रचार के लिये विदेशों से धन प्राप्त करती है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान इन संस्थाओं को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और यह धनराशि कितनी थी जो केवल